भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1269
मंगलवार, 11 फ़रवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक)को उत्तरार्थ

सहकारी बैंकों के लिए साझा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म

†1269. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में सहकारी बैंकों को निःशुल्क साझा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल राज्य से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): नाबार्ड ने अपनी विकासात्मक भूमिका के भाग के रूप में वर्ष 2011 में कोर बैंकिंग सोल्यूशन (CBS) पर ऑनबोर्ड होने के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को सहायता प्रदान की थी। 211 ग्रामीण सहकारी बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जा रहे दो CBS क्लाउड की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में नाबार्ड इन बैंकों को अपने CBS सिस्टमों को अपग्रेड करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), अर्थात् नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) को भारत में शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के अम्ब्रेला संगठन (UO) के रूप में स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित आधुनिक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद प्रदान कर सक्षम बनाने के साथ उनकी आईटी लागत को उल्लेखनीय रूप से घटाने के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय आईटी अवसंरचना प्रदान करके एक प्रमुख कर्ताधर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र को डिजिटली परिवर्तित करना हैं।

नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) कानूनी टेम्पलेट, प्रापण प्रक्रिया/टेम्पलेट, आईटी नीति/प्रक्रिया मार्गदर्शन, बुनियादी प्रौद्योगिकी सलाह/परामर्श, आईटी उपस्करों के लिए दर निर्धारण, आदि जैसी कतिपय सेवाएं निशुल्क प्रदान करेगा ।

(ग) जी नहीं, मान्यवर।

(घ) उत्पन्न नहीं होता हैं ।

*****